रणजीत टाइम्स

वर्ष : 1, अंक: 110 इंदौर, बुधवार 23 अप्रैल 2025

RNI-NO.MPHIN/2015/64585

DIGITAL EDITION

निगम में स्टाम्प शुल्क घोटाले का पर्दाफाश

36 लाख में रजिस्ट्री का चौंकाने वाला खेल

» इंदौर

संपत्ति पंजीयन के नाम पर चल रहे भ्रष्टाचार का एक नया गिरोह उजागर हुआ है, जिसने शिकायतकर्ताओं के होश उड़ा दिए हैं। आमतौर पर ५ से १० हजार रुपए में वकील या स्टाम्प वेंडर दस्तावेजों की रजिस्ट्री पूरी करा देते हैं, लेकिन नगर निगम ने मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल के पक्ष में हुकमचंद मिल की जमीन की रजिस्ट्री के लिए ३६ लाख रुपए से अधिक की फीस अदा की। यह रजिस्ट्री संपदा १.० पोर्टल के माध्यम से २८ मार्च 2025 को कराई गई, जबकि सरकार पहले ही संपदा २.० के जरिये घर बैठे रजिस्ट्री की सुविधा दे चुकी है। फिर भी नगर निगम ने महंगी, पुरानी पद्धति का ही सहारा लिया, जिससे भारी लोकलुभावन कमीशन का भुगतान संभव हुआ।

स्टाम्प वेंडर की सामान्य फीस एक लाख से कहीं कम रहती है, लेकिन इस रजिस्ट्री में डेढ़ फीसदी के आधार पर ३६ लाख रुपए से अधिक की कमिशन राशि दी गई। साथ ही जब सरकारी विभागों को आपस में संपत्ति हस्तांतरण पर स्टाम्प शुल्क से छूट का अधिकार है, तब मंगलवार को हुकमचंद मिल की ज़मीन की कीमत २१८ करोड़ ६४ लाख रुपए बताकर २० करोड़ से अधिक स्टाम्प शुल्क अदा करना बड़े सवाल उठाए बिना नहीं रहा सकता। गृह निर्माण मंडल भोपाल स्वयं लीज डीड और विक्रय पत्र तैयार करता है, तो नगर निगम को भी लीज, सब-लीज और गिरवीनामे जैसे दस्तावेज़ स्वयं तैयार करने चाहिए थे, न कि बाहरी सेवा प्रदाता को करोड़ों रुपये चुकाने चाहिए थे। इस पूरे मामले ने कांग्रेस सहित विपक्षी दलों को आक्रोशित कर दिया है। पंजीयन कार्यालय अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रशांत द्विवेदी का कहना है कि संपदा २.० पोर्टल का लाभ न उठाकर संपदा १.० का विकल्प चुनना साबित करता है कि निगम अपनी जेबें भरना चाहता था। उन्होंने लोकायुक्त में तत्काल शिकायत दर्ज कराने और सभी संबंधित दस्तावेजों की ऑडिटिंग कराने की मांग उठाई है। इस भ्रष्टाचार ने सामान्य नागरिकों के मन में सरकारी संस्थाओं पर से विश्वास दूर कर दिया है, क्योंकि लोग सोचने लगे हैं कि बड़ी रकम का लेनदेन करते समय भी भ्रष्टाचार की छाया से कैसे बचें। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की हेराफेरी से बचने के लिए पारदर्शी ई-रेजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आवश्यक है। संपदा २.० पोर्टल की सुविधाओं में विशेष सुरक्षा तंत्र, भुगतान की पारदर्शिता और कम फीस जैसे लाभ हैं, जो सभी को समान रूप से उपलब्ध कराए जाने चाहिए। यदि निगम समय पर इस पोर्टल का उपयोग करता, तो आम जनता को भी सरकारी विभागों की खुली नीतियों का फायदा मिलता और अरबों रुपए की बचत हो सकती थी।नगर निगम के अफसरों ने फिलहाल कोई ठोस जवाब नहीं दिया है, लेकिन बताया गया है कि जांच के आदेश दे दिए गए हैं।

राम को मानते पर... राम की नहीं मानते

आदित्य शर्मा

इंदौर। फिर दलित समाज के दूल्हे को मंदिर के अंदर जाने से रोका अखिल भारतीय राष्ट्रीय बलाई महासंघ के अध्यक्ष मनोज परमार ने सोशल मीडिया के माध्यम से किया कड़ा विरोध राउ विधानसभा के गांव बीजलपुर मुंडी में दलित दूल्हे को मंदिर के अंदर जाने से रोका गया जिसका विरोध समस्त दलित समाज ने किया एवं मौके पर प्रशासन भी मौजूद था परन्तु दलित समाज के दूल्हे को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया।

राम को मानने वाले क्यों राम की नहीं मानते है..

जहां एक और संपूर्ण हिंदू एवं सनातन समाज राम को मानता हे परन्तु राम की नहीं मानता हे,जहां एक और भगवान राम द्वारा सबरी के झूठे बेर खाते हे वही आज सबरी के वंशज उनके दर्शन को तरस रहे हे।

कब होगी बंद ये कू प्रथा- अब देखने वाली बात हे की कब हमारे देश ये कु प्रथा बंद होगी कब हर समाज हर व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त होगे।

क्या राम सिर्फ दबंगों के दलितों के नहीं

क्या भगवान राम सिर्फ दबंगों के हे दलितों के नहीं हे क्या, क्या दलित सनातनी या हिंदू नहीं हे क्या क्या दलित अपने प्रभु के दर्शन के लिए ऐसे ही तरसेंगे क्या।

महापौर पुष्यमित्र भार्गव की रूस यात्रा संबंधों को नई ऊँचाई, इंदौर के नवाचारों की वैश्विक प्रस्तुति

एम हकीम की विशेष रिपोर्ट

मॉस्को- इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव रूस (मॉस्को) की पाँच दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस दौरे का उद्देश्य भारत-रूस द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ करना, इंदौर के सफल शहरी नवाचारों को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करना, तथा व्यापारिक और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करना है। मॉस्को में आयोजित दूसरे राष्ट्रीय नगर मंच के उद्घाटन सत्र में पुष्यमित्र भार्गव ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए शहरी नियोजन, बुनियादी ढाँचे, स्वच्छता एवं नागरिक सुविधाओं में भारत के अनुभव साझा किए। इस मंच पर उनकी उपस्थिति ने भारत की 'स्मार्ट सिटी' योजनाओं और इंदौर के सतत विकास मॉडल को विशेष रूप से रेखांकित किया कार्यक्रम के दौरान विश्वभर से आए नगर प्रशासकों और अधिकारियों के साथ संवाद किया गया। एक भावनात्मक फोटो सत्र में सांस्कृतिक विविधता, सहयोग और साझा आकांक्षाओं की सुंदर झलक देखने को मिली।

महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने भारतीय दूतावास पहुँचकर भारत के राजदूत विनय कुमार से शिष्टाचार मुलाकात की। महापौर पुष्यमित्र भार्गव द्वारा भारत के राजदूत विनय कुमार के साथ इंदौर और मॉस्को के बीच शहरी नवाचारों, विशेषकर वेस्ट मैनेजमेंट, रोड क्लीनिंग सिस्टम, और डिजिटल नगर प्रशासन में सहयोग की संभावनाओं पर सार्थक चर्चा की ,चर्चा में भार्गव ने इंदौर नगर निगम द्वारा मॉस्को मॉडल से क्या सीखा जा सकता है, इस पर ध्यान केंद्रित करते हुए द्विपक्षीय शैक्षणिक यात्राओं एवं तकनीकी सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया।

महापौर ने भारतीय व्यापार संगठन (Indian Business Alliance) द्वारा आयोजित एक भव्य सांस्कृतिक एवं नेटवर्किंग कार्यक्रम में भाग लिया। यह आयोजन रूस में बसे भारतीय उद्यमियों, व्यावसायिक संगठनों और स्थानीय अधिकारियों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए आयोजित किया गया था।कार्यक्रम में श्री भार्गव ने मंच से मध्यप्रदेश की निवेश संभावनाओं, इंदौर के स्टार्टअप ईकोसिस्टम और व्यापारिक अनुकूलता की जानकारी दी और रूस-भारत के बीच व्यापार में मध्यप्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। महापौर ने रूस स्थित तमिल कुटुम्बकम संगठन द्वारा आयोजित तमिल नववर्ष समारोह में भी भाग लिया। उन्होंने भारतीय संस्कृति और परंपराओं के अंतरराष्ट्रीय मंच पर उत्सव के रूप में प्रसार की सराहना की। इस आयोजन में भारतीय राजदूत विनय कुमार और रूस में बसे सैकड़ों भारतीयों ने हिस्सा लिया। इस यात्रा में महापौर द्वारा इंदौर की पहचान 'स्वच्छता की राजधानी' के रूप में प्रस्तुत करते हुए, नगर प्रबंधन, जन सहभागिता, और नवाचारों के मॉडल को साझा किया गया। उन्होंने इंदौर के 7 बार स्वच्छता में प्रथम आने के पीछे की कार्यप्रणाली और नागरिक सहयोग की भूमिका को रेखांकित किया महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा मॉस्को यात्रा मेरे लिए न केवल व्यक्तिगत गर्व की बात है, बल्कि यह इंदौर और भारत के शहरी विकास मॉडल को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का एक दुर्लभ अवसर भी है। इन आयोजनों ने भारत और रूस के बीच सहयोग के कई नए द्वार खोले हैं।

निर्विचार ध्यान तनाव, रोग, शोक आदि का

सहज उपचार है

वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान्
कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवताः ।
आत्मैक्यबोधेन बिना विमुक्तिः न सिध्यति ब्रह्मशतान्तरेऽपि ॥
श्री आदिशंकराचार्य

प. पूज्य श्रीमाताजी प्रणित सहजयोग आत्मबोध या आत्मतत्व की बात करता है। जब हम आत्म तत्व की बात करते हैं तो हमें लगेगा कि ये बड़ा जटिल विषय है। आत्मा-परमात्मा, ये बातें हमें रोजमर्रा के जीवन में उपयोग में आनेवाली नहीं लगती। परंतु जीवन में हम सभी कुछ न कुछ खोज रहे हैं, और हमारी ये खोज तभी पूर्ण होगी जब हम हमारे आत्मतत्व को जान जाएंगे। सहजयोग में जब साधक को आत्मसाक्षात्कार प्राप्त होता है तब उसे यह अनुभूति उसके हृदय में और उसके सूक्ष्म शरीर पर होती है।

परंतु आज के विज्ञान के युग में हम भ्रमित हैं तथा माया और भ्रम का प्रभाव इतना अधिक है कि कई बार मानव सत्य को समझ नहीं पाता। बाहर का आडंबर, कर्मकांड, छद्म, कट्टरता, अंधविश्वास को ही धर्म या योग समझ लेता है।

इसलिये श्री आदिशंकराचार्य ने अपने शिष्यों को ग्रंथ 'विवेकचूडामणि में वैज्ञानिक दृष्टीकोण से सत्य अनुभव करने को कहा। उपरोक्त वर्णित श्लोक में वे कहते हैं, भले ही कोई शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करे, सभी देवताओं का पूजन करे, सभी प्रकारके कर्मकांड करे, देवताओं का भजन करे परंतु जब तक जीव ध्यान के माध्यम से आत्मा में पूर्ण रूप से स्थापित नहीं होता तब तक मुक्ति नहीं मिल सकती। भले ही करोड़ो वर्ष क्यों न बीत जायें। अर्थात मोक्ष के लिये आत्मा में स्थापित होना जरूरी है।

प.पू. श्रीमाताजी कहते हैं कि, आत्मसाक्षात्कार पाये बिना आत्मा में स्थित नहीं हो सकते। और जब आपको आत्मसाक्षात्कार प्राप्त होता है तो आप चित्त को अंतर्मुखी बनाकर अपने हृदय में या सहस्त्रार चक्र यानि कि ब्रह्मरंध्र पर स्थिर करने की कला सीख सकते हैं। और आप भूत व भविष्य के विचारों से मुक्त होकर वर्तमान में स्थित हो जाते हैं। निर्विचार ध्यान का अनुभव आपको अंदर से शक्तिवान और आनंदमयी बना देता है। समस्त तनाव, परेशानियां, रोग, शोक आदि से आप मुक्त हो जाते हैं। इस अद्भुत व अकल्पनीय अनुभव को प्राप्त करने हेतु सहजयोग ध्यान को एक अवसर अवश्य प्रदान करें। नज़दीकी सहजयोग ध्यान केंद्र की जानकारी टोल फ्री नंबर 1800 2700 800 से प्राप्त कर सकते हैं या वेबसाइट sahajayoga.org.in पर देख सकते हैं।

आंखो पर पट्टी बांध कर अंतर ज्ञान से बताया नोट की कीमत और नम्बर

स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से आयोजित हैप्पी स्ट्रीट आनंदम में मासूम बच्चे ने आंखों पर पट्टी बांध कर अंतर ज्ञान का प्रदर्शन किया। बालक ने बंद आंखो से ना सिर्फ कितने का नोट हैं, बल्कि उसका रंग ओर नम्बर तक बता कर सबको आश्चर्य चकित कर दिया।

आम नागरिकों को तनाव पूर्ण जिदगी व सेहत के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से हैप्पी स्ट्रीट आनंदम का आयोजन किया गया। जिसमें शामिल सभी उम्र के लोगों ने जुंबा नृत्य और खेल के साथ व्यायाम किया। इस दौरान 12 साल के बालक तनुष लाखन अपनी प्रतिभा से सबको आश्चर्य चकित कर दिया। उसने आंखों पर पट्टी बांध कर पेन का रंग बताया बाद में नोट की कीमत फिर उसका नम्बर तक बता दिया। यही नहीं एक पन्नी में रखी दो रंग की गोलियों के रंग भी बता दिए।

हैप्पी स्ट्रीट आनंदम के आयोजन में बड़ी संख्या में शामिल पुरुष, महिलाओं व बच्चों ने जुंबा नृत्य, योग किया साथ ही गेम खेले। करीब दो घंटे तक चले इस आयोजन में सभी तनाव से दूर रहे।

कार्यक्रम में सौरव शर्मा,डॉ अनुपम श्रीवास्तव, संगीत, संगीत माहेश्वरी, राजेश पाटीदार, रचना विजयवर्गी, कैप्टन जितेंद्र सिंह, मेजर अवधेश गुप्ता, राकेश कनोजिया, प्रेरणा यादव, नरेश कनोजिया, संतोष सर आदि मौजूद थे। इस आयोजन में माउंट लिट्रा जी स्कूल के तारिक कुरेशी व उनकी टीम का विशेष सहयोग रहा। अगले रविवार को इस आयोजन में अनेक प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी विजेताओं को नगद राशि पुरस्कार के रूप में दी जाएगी।

रणजीत टाइम्स
इंदौर, बुधवार 23 अप्रैल 2025
03
DIGITAL EDITION

मध्यप्रदेश में इलेक्ट्रिक बसों से शुरू होगी यातायात क्रांति

इंदौर

मध्यप्रदेश की सड़कों पर अब पारंपरिक बसों के धुएँ की जगह बिजली की चुपचाप दौड़ सुनाई देगी। केंद्र सरकार के तहत देश के 88 शहरों में कुल 6,500 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें परिचालित करने की योजना के अंतर्गत राज्य में इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन तथा सागर छह शहरों में 582 इलेक्ट्रिक बसों का आगमन होने जा रहा है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना में इंदौर को 150 बसें, सागर को 50 बसें तथा बाकी चार नगरों को 100-100 ई-बसों का लोक-परिवहन सुगम बनाए रखने के लिए प्रावधान किया गया है।

इन 582 बसों में 472 मिडी बसें होंगी जिनमें 26 सीटें उपलब्ध हैं तथा शेष दस बसें 21 सीटों के मिनी कैटरिगरी की हैं। यात्रियों की सुविधा और सादगी को ध्यान में रखते हुए किराया मात्र दो रुपये प्रति किलोमीटर तय करने की उम्मीद जताई जा रही है जिससे दैनिक यात्रियों का भार जन साधन से स्थानांतरित होगा और निजी वाहन निर्भरता कम होगी। बदले हुए इन किराया दरों से चालक-कंडक्टर व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालने वाली ग्रीन सेल मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड के साथ-साथ यात्रा सस्ती बनाए रखने का दायित्व केंद्र और राज्य की फंडिंग साझेदारी सुनिश्चित करेगी। छह शहरों में कुल नौ चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे जिनकी अनुमानित लागत लगभग 60 करोड़ रुपए आंकी गई है। इनमें इंदौर, भोपाल और ग्वालियर में दो- दो स्टेशन तथा जबलपुर, उज्जैन और सागर में एक-एक स्टेशन बनेगा।

परियोजना के लिए हाईटेंशन लाइनों का विस्तार 41 किलोमीटर लंबा होगा जिससे इन बसों का निर्बाध आवंटित पावर सप्लाई सुनिश्चित की जा सकेगी। इसका पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी तथा राज्य पर किसी अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं आएगा। इलेक्ट्रिक बसों को पर्यावरण-मित्र घोषित करते हुए प्रशासन ने उन्हें पांच सर्विलांस कैमरों, पैसेंजर काउंटिंग मशीन और दिव्यांग यात्रियों के लिए व्हीलचेयर क्रेन जैसी सुविधाओं से लैस करने का निर्णय लिया है। इस मॉडल के तहत संचालन, मेंटेनेंस तथा स्टाफिंग ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) प्रारूप पर आधारित होगी, जिसमें कंपनी अगले बारह वर्षों तक रख-रखाव एवं मानव संसाधन प्रबंधन का दायित्व लेगी। केंद्र सरकार 22 प्रतिशत एवं राज्य सरकार शेष खर्च को योजना के तहत वहन करेंगी, जबकि कंपनी 58.14 प्रतिशत योगदान देगी। यह पहल न केवल सार्वजनिक परिवहन को अधिक किफायती, सुरक्षित एवं सुलभ बनाएगी, बल्कि विजयनगरों में बढ़ते प्रदूषण के खतरे को भी काफी हद तक कम करेगी। विशेषज्ञ मानते हैं कि इलेक्ट्रिक बसों के नियमित परिचालन से एक वर्ष में लाखों लीटर पेट्रोल-डीजल की बचत होगी और वार्षिक तौर पर हजारों टन कार्बन उत्सर्जन में कटौती मिलेगी। इस प्रकार मध्यप्रदेश का यह प्रोजेक्ट सरकार की स्वच्छ ऊर्जा नीति और "हवा पानी बदलो" अभियान का एक मजबूत स्तंभ साबित होगा, जो आने वाले वर्षों में राज्यों को भी विद्युत-आधारित सार्वजनिक परिवहन अपनाने के लिए प्रेरित करेगा।

थाना खजराना पुलिस की बड़ी कार्रवाई

अवैध शराब के साथ एक आरोपी गिरफ्तार

इंदौर। खजराना थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से लगभग 1,00,000 मूल्य की कार और 38,400 मूल्य की 480 देशी सफेद शराब की क्वार्टर जब्त की गई हैं। कुल जप्त माल की कीमत 1,38,400 आंकी गई है।

पुलिस पूछताछ में आरोपी ने कबूला कि वह नशे की लत को पूरा करने के लिए सस्ते दामों पर शराब खरीदता था और फिर नशे के आदि अन्य लोगों को ऊंचे दामों पर बेचता था। मामले में आरोपी से अवैध शराब की खरीद–फरोख्त में शामिल अन्य लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है।

यह कार्रवाई इंदौर शहर में अवैध शराब और अपराध पर नियंत्रण हेतु पुलिस आयुक्त श्री संतोष कुमार सिंह, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त श्री अमित सिंह, पुलिस उपायुक्त झोन 02 श्री अभिनय विश्वकर्मा, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त झोन 02 श्री अमरेन्द्र सिंह, तथा सहायक पुलिस आयुक्त खजराना श्री कुंदन मण्डलोई के निर्देशों पर की गई। इन निर्देशों के अनुक्रम में थाना खजराना प्रभारी निरीक्षक मनोज सिंह सेंधव ने एक विशेष टीम गठित कर गोपनीय रूप से सूचना संकलन और निगरानी कार्य प्रारंभ किया। इसी अभियान के तहत थाना खजराना की टीम स्कीम नं. 134 के पास स्टार चौराहा स्थित एक खाली मैदान में गश्त कर रही थी, जहां एक संदिग्ध व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगा। टीम ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम ईमरान शाह उर्फ इमरान गोरी पिता युनूस शाह (उम्र 32 वर्ष), निवासी HBK गार्डन के सामने, नई सड़क, खजराना, इंदौर बताया। नियमित तलाशी के दौरान आरोपी की कार की डिक्की से 480 क्वार्टर अवैध देशी सफेद शराब बरामद हुई। आरोपी ने पूछताछ में यह भी स्वीकार किया कि वह स्वयं शराब का आदी है और इस लत के चलते शराब को सस्ते दामों में खरीदकर दूसरों को ऊंचे दामों पर बेचता था। थाना खजराना में आरोपी के खिलाफ धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। पुलिस आरोपी से शराब के नेटवर्क और उसके अन्य साथियों की जानकारी जुटा रही है, जिसके आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

इस कार्रवाई में निरीक्षक मनोज सिंह सेंधव, उप निरीक्षक घनश्याम मिश्रा, अनिल गौतम, सहायक उप निरीक्षक राकेश परमार, प्रधान आरक्षक पंकज सांवरिया, अजीत यादव, नरेश चौहान, आरक्षक प्रदीप सूर्यवंशी, शुभम सिंह, अंशु, आनंद, पुष्पेंद्र और अंकित की सराहनीय भूमिका रही।

फिर डराने लगा कोरोना-इंदौर में दो नए मरीज, एक की मौत

मध्यप्रदेश में कोरोना संक्रमण ने एक बार फिर दस्तक दी है। इंदौर शहर में कोरोना के दो नए मरीज सामने आए हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। दोनों ही मरीजों को अलग–अलग बीमारियों के कारण निजी अस्पताल में भर्ती किया गया था, लेकिन जांच के दौरान उनमें कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई।

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, इन मरीजों को लम्बे समय से सर्दी और खांसी की शिकायत थी जो सामान्य उपचार के बावजूद ठीक नहीं हो रही थी। इसी के चलते चिकित्सकों ने इनकी फ्लू पैनल जांच कराई जिसमें कोरोना वायरस की उपस्थिति पाई गई। इनमें से एक मरीज, 74 वर्षीय महिला जो इंदौर के पश्चिमी क्षेत्र की निवासी थीं, पहले से किडनी संबंधी रोग से ग्रसित थीं और गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती की गई थीं। उन्हें सीवियर सेप्टिक की शिकायत भी थी। सोमवार को उनकी स्थिति अत्यधिक बिगड़ने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। वे कोमॉर्बिडिटी की शिकार थीं और कोरोना ने उनकी हालत और जटिल बना दी। वहीं, दूसरा मरीज एक युवक है जिसकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। उसे अस्पताल के एक अलग वार्ड में आइसोलेट किया गया है और इलाज जारी है। डॉक्टरों के अनुसार युवक की हालत फिलहाल खतरे से बाहर है। अरबिंदो अस्पताल के निदेशक डॉ. विनोद भंडारी ने जानकारी दी कि कुछ मरीजों में जब सामान्य वायरल लक्षण लंबे समय तक बने रहते हैं, तो एक विशेष फ्लू पैनल जांच की जाती है, जिसमें कोरोना की जांच भी शामिल होती है। इसी प्रक्रिया में युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया।

अस्पताल प्रशासन द्वारा कोरोना से संबंधित सभी दिशा–निर्देशों का पालन किया जा रहा है।

बचपन को नकरात्मक ऊर्जा से संरक्षित रखता है सहजयोग

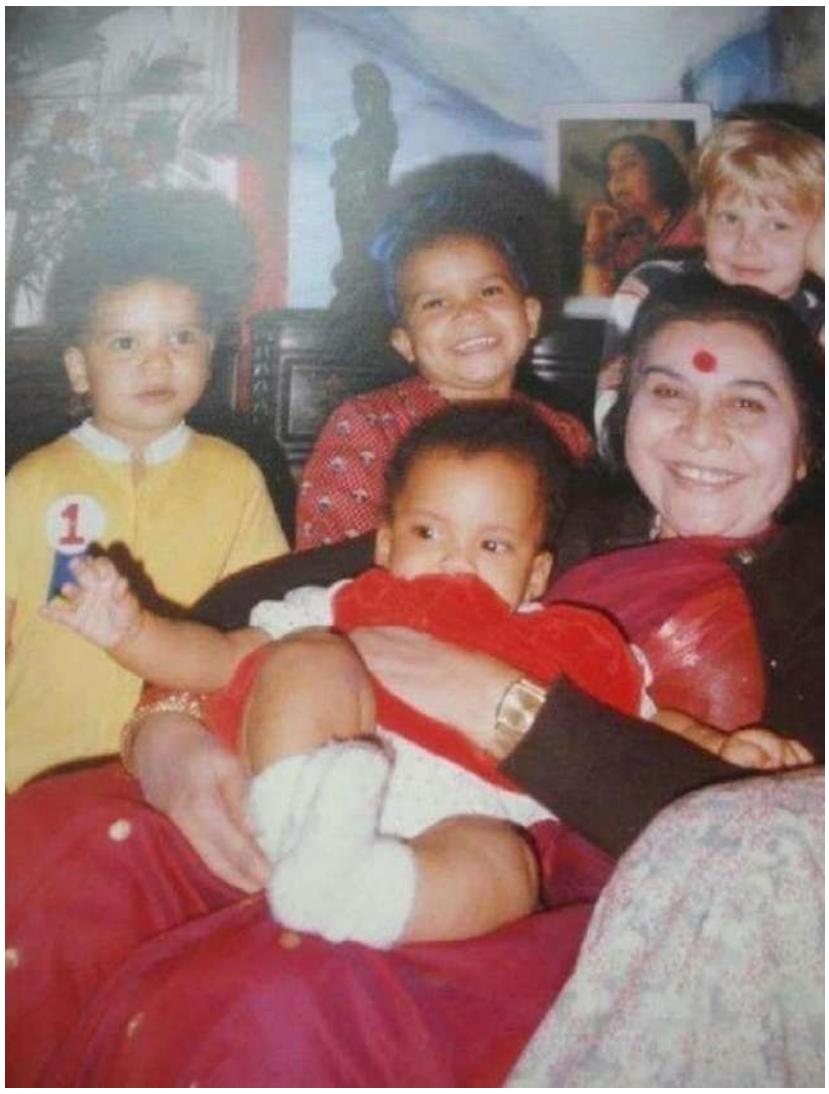

परम पूज्य श्री माताजी निर्मला देवी के अनुसार, सहज योग मात्र वयस्कों या अभिभावकों के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है अपितु बच्चों में भी सहयोग का विकास किया जाना चाहिए ।

अधिकांशतः सब यह सोचते हैं कि कुंडलिनी जागरण या आत्मा का योग होने के कारण इसका अभ्यास वयस्कों को करना चाहिए, परंतु श्री माताजी ने अनेक अवसरों पर अपने अमृत वचनों में स्पष्ट रूप से वर्णन किया है कि बच्चे स्वयं श्री गणेश का अंश होते हैं, उनमें अबोधिता तथा पवित्रता जैसे गुण अंतर्जात ही होते हैं तथा बच्चे अनेक प्रकार की नकारात्मकताओं से स्वयं ही दूर होते हैं। यदि बालपन से उन्हें सहजयोग में उतारा जाए तो वह अल्प समय में ही सहज में प्रतिस्थापित हो जाते हैं ।जैसे - जैसे उम्र का विकास होता है मनुष्य के अंदर से अनेक गुणों का ह्रास होता जाता है परंतु यदि बालपन से ही बच्चे सहज जीवन का अंग होते हैं, तो उनमें विवेकशीलता, बुद्धिमत्ता तथा अनुशासन सदैव बना रहता है। श्री माताजी के अनुसार, बच्चों की शिक्षा का अभिभावकों को विशेष ध्यान रखना चाहिए तथा उन्हें उनकी रुचि अनुसार विद्या अध्ययन का अवसर प्रदान करना चाहिए। सहजयोग विद्यार्थियों में एकाग्रता स्थापित करने में अत्यंत मददगार होता है साथ ही समाज में व्याप्त अनेक बुराइयों व नकारात्मक चीजों से सहजयोगी बालक सदैव संरक्षित रहता है। अनेक ऐसे उदाहरण हैं जिसमें आत्म साक्षात्कारी सहज योगी बालकों ने अपने मनचाहे क्षेत्र में उच्च सफलताएं अर्जित कर अपना कैरियर बनाया है । मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे ही स्वस्थ समाज का निर्माण करने में सक्षम हो सकते हैं अतः व्यक्ति में सहज योग की प्रतिष्ठा बचपन में ही की जानी चाहिए ताकि वे श्री माता जी की कृपा से समाज के जागरूक नागरिक होने का कर्तव्य निभा सकें तथा धर्म की स्थापना में सहायक हों। पूर्णतः निःशुल्क सहजयोग के अनगिनत लाभों से लाभान्वित होने हेतु जानकारी निम्न साधनों से प्राप्त कर सकते हैं टोल फ्री नं – 1800 2700 800 बेवसाइट - sahajayoga.org.in

कितनी भी व्यस्तता हो,फिट रहने की कोशिश करें : प्रशांत शर्मा

ऋषि गोस्वामी शिवपुरी

कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया होता है और स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन होता है,शिवपुरी जिले के पिछोर सर्किल के इंचार्ज SDOP प्रशांत शर्मा ने आज ये बात हमारे संवाददाता से कही कि आप कितने भी व्यस्त क्यों न हों लेकिन खुद को फिट रखने का प्रयास जरूर करें ,दरअसल आज विश्व पृथ्वी दिवस है और कल शर्मा जी की बिटिया वैदेही का जन्मदिन भी,इसी उपलक्ष्य में आज पर्यावरण सुरक्षा का संदेश आमजन को देने हेतु श्री शर्मा ने पिछोर से खनियाधाना तक की दूरी साइकिल से तय की और संदेश दिया कि पर्यावरण की सुरक्षा और खुद को फिट रखना ये सभी को अपने जीवन में शामिल करना चाहिए,श्री शर्मा ने कहा कि आजकल लगभग सभी लोग किसी ना किसी कारण से फिजिकल एक्टिविटी से दूर होते जा रहे हैं जिससे उनके स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ रहा है उन्होंने सभी से आग्रह किया है कि सभी स्वस्थ रहने और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अवश्य प्रयास करें,उन्होंने इस 20 किमी की साइकिल यात्रा पर्यावरण और अपनी बिटिया को समर्पित की है।

अपनी अलग कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं श्री शर्मा

हम आपको बता दें कि पिछोर पुलिस अनुभाग के मुखिया श्री प्रशांत शर्मा बेहतरीन पुलिसिंग के साथ साथ बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं,श्री कविताएं भी लिखते हैं,बच्चों को स्कूल कॉलेज में पहुंचकर करियर मार्गदर्शन भी देते हैं एवं अन्य सामाजिक सांस्कृतिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं।

समस्त उचित मूल्य दुकानों के विक्रेताओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई

जनपद पंचायत बागली के सभा कक्ष में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बागली आनंद मालवीया की अध्यक्षता में एवं सहायक आपूर्ति अधिकारी अभिषेक मोर के द्वारा अनुभव बागली की समस्त उचित मूल्य दुकानों के विक्रेताओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई । बैठक में सभी विक्रेताओं को उचित मूल्य दुकान की POS मशीन से सभी संबंधित हितग्राहियों की शत प्रतिशत ई केवाईसी 30 अप्रैल 2025 तक किए जाने हेतु एसडीएम बागली द्वारा निर्देशित किया गया । साथ ही उचित मूल्य दुकान चापड़ा 2004026 , गुराडियाकला 2004027 , मुकुंदगढ़ 2004028 , भमोरी 2004029 , आदर्श भंडार हाटपीपल्या 2009006 और चापड़ा समिति द्वारा संचालित दुकान 2009003 के विक्रेता द्वारा ekyc में संतोषजनक कार्य नहीं करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । SDM बागली द्वारा दुकान के विक्रेताओं को , छोटे बच्चों के फेस ekyc , मोबाइल ऐप से निर्धारित समयावधि में करने और मृत , विवाहितों की सूची कार्यालय में प्रदान करने के निर्देश दिए गए अन्यथा की दशा में विक्रेताओं पर म0 प्र0 सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) 2015 के प्रावधानों के तहत करवाई करने के निर्देश दिए ।

विद्यार्थी परिषद ने आईटीआई कॉलेज को ताला मार किया धरना प्रदर्शन

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई हाटपिपल्या द्वारा श्री कैलाश जोशी आई टी आई महाविद्यालय में हो रही अनियमितता को लेकर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं एवं विद्यार्थियों द्वारा आज महाविद्यालय के ताला बंद एवं घेराव किया नगर मंत्री प्रवीण यादव ने बताया कि 8 अप्रैल को महाविद्यालय के प्राचार्य को कॉलेज में हो रही पानी की समस्या एवं हो रही तोड़ फोड़ को लेकर कर ज्ञापन सोपा गया था परंतु कॉलेज प्रशासन द्वारा इस मामले पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया जिसको लेकर आज महाविद्यालय के समस्त छात्र शक्ति एवं विद्यार्थी परिषद के

कार्यकर्ता ने कॉलेज का ताला लगाकर धरना प्रदर्शन किया गया धरना प्रदर्शन के चलते हाटपिपल्या की तहसीलदार मोके पर पहुँची विद्यार्थी परिषद के देवास जिला संयोजक प्रणय पांचाल ने तहसीलदार को पूरे मामले से अवगत कराया एवं मांग की छात्र शक्ति को आने वाली यह गंभीर समस्या का तत्काल प्रभाव के साथ निराकरण किया जाए अन्यथा यह धरना प्रदर्शन बंद नहीं होगा इस मांग को तहसीलदार ने संहज्ञान में लिए एवं तत्काल समस्या का समाधान किया विद्यार्थी परिषद की जीत हुई व धरना प्रदर्शन बंद किया इस मौके पर महाविद्यालय छात्र शक्ति एवं विद्यार्थी परिषद के नगर इकाई के अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे-

संविदा स्वास्थ्य कर्मियों का प्रदेशव्यापी आंदोलन

वादाखिलाफी के खिलाफ फूटा आक्रोश, 23 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे 32 हजार कर्मचारी

मध्य प्रदेश। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया है। सरकार द्वारा किए गए वादों को न पूरा किए जाने से आहत होकर प्रदेशभर के हजारों संविदा कर्मचारी 23 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा कर चुके हैं। इस आंदोलन की शुरुआत बड़वानी जिले से हुई, जहां मंगलवार को सैकड़ों की संख्या में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया और भगवान सिद्धेश्वर मंदिर से जिला स्वास्थ्य विभाग तक रैली निकालकर सरकार को अपने आक्रोश का स्पष्ट संदेश दे दिया। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारी पहले सिद्धेश्वर मंदिर पहुंचे और वहां भगवान से न्याय की प्रार्थना की। इसके बाद वे रैली के रूप में स्वास्थ्य विभाग कार्यालय पहुंचे, जहां मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. सुरेखा जमरे को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन में कर्मचारियों ने सरकार से उन सभी वादों को पूरा करने की मांग की जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 4 जुलाई 2023 को भोपाल में आयोजित महापंचायत में किए गए थे। कर्मचारियों का आरोप है कि जिन सुविधाओं को पहले बहाल किया गया था, अब सरकार उन्हें एक-एक कर वापस ले रही है, जिससे हजारों कर्मचारियों और उनके परिवारों के सामने संकट खड़ा हो गया है।

संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अशोक कनाडे ने बताया कि विभाग में वर्षों से 50% पद रिक्त पड़े हैं, लेकिन इन पदों पर अभी तक संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं किया गया। कर्मचारियों की सबसे प्रमुख मांग है कि उन्हें छुट्टियों के अधिकार (ईएल) और मेडिकल सुविधाएं वापस दी जाएं, जो पहले उपलब्ध थीं लेकिन अब हटा दी गई हैं। इसके अलावा अनुबंध प्रथा को पूरी तरह खत्म करने और अप्रेजल सिस्टम जैसी व्यवस्थाओं को समाप्त करने की मांग भी आंदोलन का एक अहम हिस्सा है। बड़वानी जिले में ही 800 से अधिक संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी इस आंदोलन में शामिल होने की तैयारी कर चुके हैं, वहीं पूरे प्रदेश में यह संख्या 32,000 के करीब पहुंच रही है। इस आंदोलन की गूंज प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था तक पहुंचने लगी है, क्योंकि इन कर्मचारियों की हड़ताल से अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रत्यक्ष असर पड़ना तय माना जा रहा है।

संविदा कर्मियों का यह भी कहना है कि वे सरकार के किसी बहकावे में नहीं आएंगे और जब तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक वे अपने कदम पीछे नहीं हटाएंगे। यह सिर्फ वेतन या सुविधाओं की बात नहीं है, बल्कि यह पूरे सम्मान, स्थायित्व और सुरक्षा के अधिकार की लड़ाई है, जिसे वे अब अंतिम स्तर तक ले जाने के लिए तैयार हैं। प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं संविदा कर्मचारियों के कंधों पर टिका हुआ है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें लगातार अनदेखा किया जा रहा है। वर्षों से सेवा देने के बाद भी न तो उन्हें स्थायी किया गया, न ही वे वो सुविधाएं पा सके जो नियमित कर्मचारियों को मिलती हैं। ऐसे में अब यह आंदोलन केवल एक मांग नहीं, बल्कि सरकार की नीतियों के प्रति आक्रोश का विस्फोट बनता जा रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या सरकार संविदा कर्मचारियों की इस नाराजगी को गंभीरता से लेगी? क्या एक बार फिर वही वादों का पुलिंदा तैयार कर उन्हें टालने की कोशिश की जाएगी या फिर इस बार कोई ठोस समाधान निकलेगा? आने वाले दिनों में यह आंदोलन प्रदेश की राजनीति और स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा दोनों तय कर सकता है।

स्कूलों में लगेगी मस्ती की पाठशाला

सरकारी स्कूलों के लिए मोहन सरकार का आनंद प्लान

● बच्चे सीखेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट के साथ जीवन जीने की कला

भोपाल। मप्र की मोहन सरकार अब सरकारी स्कूलों में मस्ती की पाठशाला लगाने जा रही है। दरअसल, सरकारी स्कूल की पढ़ाई बेहतर बनाने के साथ सराकार बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रही है। इसी के तहत मोहन सरकार शासकीय स्कूलों के लिए आनंद योजना लेकर आ रही है। इसके तहत अब स्कलों में कोर्स की पढ़ाई के साथ बच्चों को जीवन जीने की कला और स्ट्रेस मैनेजमेंट की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इसके लिए सरकारी स्कूलों में अलग से आनंद का एक पीरियड लगाया जाएगा, जिसमें हायर सेकंडरी के बच्चों को जीवन जीने और तनाव मुक्त रहने की कला सिखाई जाएगी। दरअसल, स्कूली बच्चों में स्ट्रेस और प्रतिस्पर्धा को देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने आनंद विभाग के साथ अनुबंध किया है। इसमें आनंद विभाग शिक्षकों को पहले ट्रेनिंग देगा, फिर वही शिक्षक बच्चों को प्रशिक्षित करेंगे। ऐसे में इसे मस्ती की पाठशाला भी कहा जा रहा है, जो बच्चों के लिए काफी फायदेमंद भी होगी।

पहली बार हायर सेकंडरी स्कूलों में मस्ती की पाठशाला - राज्य आनंद संस्थान के डायरेक्टर सत्य प्रकाश आर्य ने बताया कि पहली बार सरकारी स्कूलों में आनंद की क्लास लगाई जाएगी। नई शिक्षा नीति के तहत बच्चों को स्कूली शिक्षा देने के साथ उनको मानवीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा देना भी अनिवार्य है। इसी के तहत स्कूलों में आर्ट ऑफ लिविंग और स्ट्रेस मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके साथ ही शिक्षकों को भी 6 दिनों का प्रशिक्षण आनंद संस्थान द्वारा किया जाएगा।

2 हजार सरकारी स्कूलों से होगी शुरुआत

बता दें कि स्कूल शिक्षा विभाग पहले भी सीएम राइज और मॉडल स्कूलों में मस्ती की पाठशाला का प्रयोग कर चुका है। इसके सकारात्मक परिणामों को देखते हुए अन्य सरकारी स्कूलों में भी मस्ती की पाठशाला लगाने का फैसला लिया गया है। हालांकि, पहले चरण में 2 हजार स्कूलों में मस्ती की पाठशाला की शुरुआत होगी। इसके बाद प्रदेश के अन्य सरकारी स्कूलों के हायर सेकंडरी के बच्चों के लिए आनंद क्लास लगाई जाएगी।

इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में भी आनंद पीरियड

सरकार की मंशा है कि जिस तरह सरकारी स्कूलों में आनंद की कक्षाएं शुरु की जा रही है। इसी तरह प्रदेश के इंजीनियरिंग, मेडिकल, एनटीटीटीआर और अन्य कालेजों में भी स्ट्रेस मैनेजमेंट और आर्ट आफ लिविंग की शिक्षा दी जाए। इसके लिए राज्य आनंद संस्थान ने पूरी तैयारी कर ली है। इधर सरकारी स्कूलों में बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए 4 हजार सरकारी शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। बता दें कि अभी 24 से 29 मार्च तक सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए वर्चुअल क्लासेस भी लगाई गई थी, जिसमें 3500 से 4 हजार बच्चों ने भाग लिया था।

अब नहीं चलेगी मनमानी, मप्र में वाहन चेकिंग के लिए नई गाइडलाइन जारी

भोपाल। मध्यप्रदेश में अक्सर वाहन चेकिंग को लेकर विवाद और अवैध वसूली की शिकायतें सामने आती रहती हैं। इसे देखते हुए परिवहन विभाग ने सख्त कदम उठाते हुए नई गाइडलाइन जारी की है। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर द्वारा जारी इन निर्देशों में 8 अहम बिंदु शामिल हैं जिनका पालन अनिवार्य होगा। आदेश की अवहेलना पर संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी।

1. **अधिकारी की मौजूदगी अनिवार्य** - अब वाहन चेकिंग केवल तब की जा सकेगी जब मौके पर सहायक परिवहन उप निरीक्षक स्तर का अधिकारी उपस्थित हो। बिना अधिकृत अधिकारी के कोई भी चेकिंग कार्रवाई नहीं की जा सकेगी।
2. **वर्दी और नेम प्लेट अनिवार्य** - चेकिंग के समय सभी स्टाफ को वर्दी में रहना अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही सभी के पास नेम प्लेट होना भी जरूरी होगा जिससे उनकी पहचान स्पष्ट रहे।
3. **निजी व्यक्तियों की भागीदारी प्रतिबंधित** -चेकिंग प्रक्रिया में किसी भी निजी व्यक्ति की भागीदारी पूरी तरह से प्रतिबंधित की गई है। चालान की प्रक्रिया केवल पॉसमशीन के माध्यम से की जाएगी जिससे पारदर्शिता बनी रहे।
4. **एक बार में केवल एक वाहन की जांच** - चेकिंग यूनिट एक समय में केवल एक वाहन को ही रोकेगी और उसकी पूरी जांच होने के बाद ही अन्य वाहन को रोका जाएगा। बिना कारण 15 मिनट से अधिक किसी वाहन को रोकने पर कार्रवाई की जाएगी।
5. **रात में चेकिंग के लिए सुरक्षा उपाय जरूरी** - रात के समय चेकिंग केवल वहीं होगी जहां पर्याप्त रोशनी हो। अंधेरे में जांच के लिए स्टाफ के पास एलईडी बैटन और रिफ्लेक्टिव जैकेट होना जरूरी है। इससे दुर्घटनाओं से बचाव होगा।
6. **बॉडी वॉर्न कैमरा से होगी निगरानी** - चेकिंग के दौरान कम से कम दो बॉडी वॉर्न कैमरा चालू हालत में रहने चाहिए, जिनमें से एक लाइव मोड में हो। पूरी कार्रवाई कैमरे में रिकॉर्ड होनी चाहिए, जिससे भविष्य में शिकायत की जांच आसान हो।
7. **कैमरों की बैटरी और स्टोरेज की व्यवस्था** - सुनिश्चित किया जाएगा कि बॉडी वॉर्न कैमरे पूरी तरह चार्ज हों और उनमें पर्याप्त स्टोरेज मौजूद हो। यह जिम्मेदारी यूनिट प्रभारी की होगी।
8. **विवाद की स्थिति में कैमरे में रिकॉर्डिंग अनिवार्य** - अगर चेकिंग के दौरान ड्राइवर या किसी व्यक्ति से विवाद होता है, तो पूरी घटना कैमरे में रिकॉर्ड की जाएगी। इससे वरिष्ठ अधिकारी मामले की वास्तविकता समझ सकेंगे और निष्पक्ष निर्णय लिया जा सकेगा।

सरपंच ट्रॉफी का खिताब शाइनिंग स्टार शांतिनगर ने जीता

ग्राम पंचायत गवली पलासिया के सरपंच रवि पाटीदार संरक्षक एवं धर्मेंद्र पाटीदार आयोजक पीसीसी क्रल्ब के द्वारा रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा शासकीय स्कूल गवली पलासिया ग्राउंड पर आयोजित की गई। स्पर्धा के तहत कुल 44 टीमों ने भाग लेकर अपने खेल का उमदा प्रदर्शन दिखाया। स्पर्धा के तहत मैच का खिताब शाइनिंग स्टार शांति नगर ने अपने नाम किया। लिहाजा विजेता टीम को 25 हजार नकद एवं ट्रॉफी प्रदान की गई। इसी तरह उपविजेता पीसीसी क्रिकेट क्लब को 15 हजार नकद एवं ट्रॉफी प्रदान की गई। वहीं तीसरे स्थान पर रहे जय गणेश क्रिकेट क्लब को 5 हजार नकद एवं ट्रॉफी प्रदान की गई। वहीं स्पर्धा में मेंन ऑफ़ द सीरीज धर्मेंद्र पाटीदार (कप्तान), बेस्ट बॉलर राजीव झा, बेस्ट बैट्समैन सोनू थापा, बेस्ट फ़ील्डर आर्यन ओसारी, बेस्ट कैच नील एकवन रहे इन्हे भी अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया।

दो डर और एक फायदे की उम्मीद में छोड़ा चुनाव, केजरीवाल को उलटा भी पड़ सकता है दांव

नईदिल्ली, एजेंसी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की हार के बाद आम आदमी पार्टी (आप) ने एक चौंकाने वाला फैसला लेते हुए एमसीडी (दिल्ली नगर निगम) में मेयर चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया है। अरविंद केजरीवाल की अगुआई वाली पार्टी के इस कदम से दिल्ली में भाजपा की ट्रिपल इंजन सरकार का रास्ता साफ हो गया है। भाजपा के खिलाफ बेहद आक्रामक रुख रखने वाली आप ने आखिर क्यों बिना लड़े ही उसके सामने हथियार डाल दिया, राजनीतिक विश्लेषक इसका जवाब तलाशने में जुटे हैं। फिलहाल इतना कहा जा रहा है कि आप ने दो डर और एक फायदे की उम्मीद में एमसीडी की सत्ता आसानी से अपने हाथ से जाने देने का फैसला किया है। हालांकि, 2 साल बाद एमसीडी चुनाव में आप के लिए यह दांव उलटा भी पड़ सकता है।

आप ने भले ही यह कहकर हाई मोरल ग्राउंड लेने की कोशिश की कि चुनाव जीतने के लिए उन्हें जोड़तोड़ करना पड़ता, जो वह करना नहीं चाहती, पर सच्चाई यह है कि पार्टी जानती है कि 2022 में मिली बहुमत

अब उसके हाथ से फिसल चुकी है। पार्टी अपने पार्षदों को एकजुट रखने में नाकामयाब रही। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि पार्टी कुछ महीने पहले ही विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद लगातार दूसरी पराजय का सामना करने से डर गई। संभवतः पार्टी को इस बात की आशंका रही होगी कि लगातार दूसरी हार की खबरों से उसके कार्यकर्ताओं के मनोबल पर असर होगा और इसका प्रभाव पंजाब तक हो सकता है, जहां पार्टी अभी से विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। 2022 के अंत में हुए हुए एमसीडी चुनाव में आप ने भाजपा से 15 साल पुरानी सत्ता छीनते हुए 134 पार्षद जीते थे, जबकि भाजपा को 104 वार्ड में जीत मिली थी। करीब ढाई साल तक चले दलबदल के खेल के बाद अब भाजपा के पास 117 पार्षद हैं। जबकि आम आदमी पार्टी के पास 113 पार्षद हैं। बताया जा रहा है कि 25 तारीख को होने जा रहे मेयर चुनाव में आप को ना सिर्फ हार साफ दिख रही थी बल्कि उसे कुछ और पार्षदों के क्रॉस वोटिंग का डर था। ऐसा होने पर पार्टी की एकजुटता पर भी नए सवाल खड़े हो जाते। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की हार के बाद आम आदमी पार्टी (आप) ने एक चौंकाने वाला फैसला लेते हुए एमसीडी (दिल्ली नगर निगम) में मेयर चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया है। अरविंद केजरीवाल की अगुआई वाली पार्टी के इस कदम से दिल्ली में भाजपा की ट्रिपल इंजन सरकार का रास्ता साफ हो गया है। भाजपा के खिलाफ बेहद आक्रामक रुख रखने वाली आप ने आखिर क्यों बिना लड़े ही उसके सामने हथियार डाल दिया, राजनीतिक विश्लेषक इसका जवाब तलाशने में जुटे हैं। फिलहाल इतना कहा जा रहा है कि आप ने दो डर और एक फायदे की उम्मीद में एमसीडी की सत्ता आसानी से अपने हाथ से जाने देने का फैसला किया है। हालांकि, 2 साल बाद एमसीडी चुनाव में आप के लिए यह दांव उलटा भी पड़ सकता है। आप ने भले ही यह कहकर हाई मोरल ग्राउंड लेने की कोशिश की कि चुनाव जीतने के लिए उन्हें जोड़तोड़ करना पड़ता, जो वह करना नहीं चाहती, पर सच्चाई यह है कि पार्टी जानती है कि 2022 में मिली बहुमत अब उसके हाथ से फिसल चुकी है।

तब्लीगी जमात के विदेशियों को शरण देने का मामला, दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 के कोविड-19 महामारी के दौरान तब्लीगी जमात से जुड़े विदेशी नागरिकों को शरण देने के मामले में सोमवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इस मामले में आरोपी 70 भारतीय नागरिकों द्वारा हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थीं। आरोपी भारतीय नागरिकों के खिलाफ आईपीसी, एपिडेमिक डिजीज एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और फॉरेनर्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई थीं।

जस्टिस नीना बंसल की बेंच ने तब्लीगी जमात से जुड़े 70 भारतीय नागरिकों से जुड़े 16 एफआईआर के मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। आरोपियों पर कोविड-19 महामारी के दौरान 24 मार्च 2020 से 30 मार्च 2020 के बीच अलग-अलग मस्जिदों में विदेशी नागरिकों को शरण देने के लिए आईपीसी की धारा 188/269/270/120-बी के तहत चार्जशीट दायर की गई थी।

इन भारतीय नागरिकों द्वारा शरण पाने वाले 195 विदेशी नागरिकों के नाम भी एफआईआर में दर्ज हैं। हालांकि, अधिकांश चार्जशीट में उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं की गई या ट्रायल कोर्ट ने दोहरे खतरे के सिद्धांत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था। क्योंकि विदेशी नागरिकों के एक ही ग्रुप पर एक ही तरह के अपराधों के लिए चार्जशीट दाखिल की गई थीं।

याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील आशिमा मंडला और मंदाकिनी सिंह हाईकोर्ट में पेश हुईं। वकील आशिमा मंडला ने इस घटना के संबंध में अन्य अदालतों द्वारा दिए फैसलों को भी रिकॉर्ड पर रखा।

तब्लीगी जमात के आयोजन से जुड़ा यह मामला पब्लिक हेल्थ पर इसके कथित प्रभाव और महामारी के दौरान रेगुलेटरी गाइडलाइंस के पालन के कारण कानूनी जांच के अधीन है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कोविड-19 महामारी के दौरान कथित उल्लंघन के संबंध में आईपीसी, एपिडेमिक डिजीज एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और फॉरेनर्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत भारतीय और विदेशी नागरिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थीं।

दोगुना जल मिले तभी बच सकता है दिल्ली में यमुना का जीवन, डीपीसीसी की रिपोर्ट

नई दिल्ली, एजेंसी। राजधानी दिल्ली में यमुना नदी का जीवन दोगुना जल मिलने पर ही बच सकता है। यह बात दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा तैयार एक रिपोर्ट में कही गई है। रिपोर्ट के मुताबिक मई जैसे सूखे महीने में भी नदी का नैसर्गिक बहाव (एंवायरमेंटल फ्लो) 23 क्यूमेक्स होना चाहिए। जबकि, अभी नदी का बहाव सिर्फ 10 क्यूमेक्स रहता है। यानी, नैसर्गिक बहाव के लिए कम से कम 13 क्यूमेक्स जल और होना चाहिए। राजधानी से गुजरने वाली एकमात्र बड़ी नदी यमुना है। दिल्ली के सांस्कृतिक और प्राकृतिक जीवन पर यमुना का सदियों से महत्व रहा है। लेकिन, हाल के वर्षों में यमुना का जीवन दिल्ली में समाप्त जैसा हो गया है। दिल्ली के बड़े-बड़े नालों से सीधे यमुना में गिरने वाले गंदे पानी के चलते प्रदूषण का स्तर इतना ज्यादा होता है कि नदी का जलीय जीवन काफी हद तक नष्ट हो चुका है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा तैयार रिपोर्ट में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी रुड़की के हवाले से बताया गया है कि नदी का एंवायरमेंटल फ्लो बनाए रखने के लिए जितने जल की जरूरत है।

अब शरबत जिहाद पर फंसे बाबा रामदेव, दिल्ली हाईकोर्ट ने जमकर लगाई फटकार

नई दिल्ली, एजेंसी। हमदर्द रूह अफजा पर टिप्पणी कर योग गुरु बाबा रामदेव मुश्किलों में फंस गए हैं। मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने शरबत जिहाद के मामले में उन्हें कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि रामदेव की इस बात का कोई बचाव नहीं है। टिप्पणी के बाद कंपनी ने हाईकोर्ट का रुख किया था।

उच्च न्यायालय ने कहा है कि इस बात ने अदालत की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया है। साथ ही कहा है कि इसकी कोई माफी नहीं है। कोर्ट ने रामदेव की तरफ से पेश हुए वकील को उपस्थित रहने के लिए कहा है। कंपनी ने आरोप लगाए हैं कि यह सांप्रदायिक विभाजन फैलाने का मामला है। साथ ही इसे नफरत भरे भाषण के जैसा बताया है। हमदर्द की तरफ से कोर्ट पहुंचे सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कहा, यह केस हैरान करने वाला है। यह मामला सांप्रदायिक विभाजन कराने वाला है और हेट स्पीच के समान है। इसे मानहानि के कानून के तहत संरक्षण नहीं मिल सकेगा। उन्होंने कहा है कि देश में पहले ही काफी समस्याएं हैं और इसे एक पल के लिए भी अनुमति नहीं मिलनी चाहिए।

3 अप्रैल को बाबा रामदेव ने रूह अफजा बनाने वाली कंपनी हमदर्द को लेकर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि दवा और खाद्य सामग्री बनाने वाली कंपनी अपने धन का इस्तेमाल मस्जिद और मदरसा बनाने में कर रही है। इसके बाद कंपनी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। रामदेव का एक वीडियो पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल है। इसमें वह पतंजलि के शरबत का प्रचार करने के दौरान यह कहते हुए देखे और सुने जा सकते हैं कि शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है लेकिन शरबत से जो पैसा मिलता है। उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है।

रामदेव ने कहा था, अगर आप वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे और पतंजलि का शरबत पिएंगे तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय और भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं ये 'शरबत जेहाद' है। जैसे 'लव जेहाद', 'वोट जेहाद' चल रहा है वैसे ही 'शरबत जेहाद' भी चल रहा है।

हिंदुओं को बचाने के लिए स्कॉटलैंड लाया ऐतिहासिक बिल, पहली बार हिंदूफोबिया पर उठी आवाज

एडिनबरा, एजेंसी। यूरोपीय देश स्कॉटलैंड की संसद में पहली बार हिंदू समुदाय के खिलाफ बढ़ते भेदभाव और हाशिए पर डाले जाने को लेकर एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पेश किया गया है। एल्बा पार्टी की सांसद ऐश रीगन ने यह प्रस्ताव ग्लासगो की गांधीवादी शांति संस्था की रिपोर्ट के आधार पर पेश किया है। यह कदम न केवल स्कॉटलैंड बल्कि पूरे यूरोपीय संघ में अपनी तरह का पहला प्रस्ताव है। यह प्रस्ताव स्कॉटलैंड के हिंदू समुदाय के सामने आ रही चुनौतियों, जैसे कि धार्मिक नफरत, मंदिरों पर हमले और सांस्कृतिक असहिष्णुता को प्रमुखता से उजागर करता है।

प्रस्ताव में क्या है?: स्कॉटिश संसद ने गांधीवादी शांति संस्था के कार्यों की सराहना की है। प्रस्ताव में 'हिंदूफोबिया इन स्कॉटलैंड' रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया गया है कि किस तरह से हिंदू समुदाय को भेदभाव, बहिष्करण और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ रहा है। यह प्रस्ताव अंतर-धार्मिक संवाद, सामाजिक समरसता और विविधता को बढ़ावा देने के प्रयासों को आगे बढ़ाने की अपील करता है। यह रिपोर्ट स्कॉटलैंड में हिंदू समुदाय पर केंद्रित पहली व्यापक अध्ययन है। इसके अनुसार, 5.4 मिलियन की जनसंख्या वाले स्कॉटलैंड में हिंदुओं की संख्या महज 0.3प्रतिशत है और इस छोटे समुदाय को असमानता, मंदिरों पर हमले, जातिगत टिप्पणियां और दुर्व्यवहार जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सरकार द्वारा पेश किए गए इस बिल को

लेकर भारतीय मूल के नेताओं की प्रतिक्रिया आई है।

भारतीय काउंसिल ऑफ स्कॉटलैंड के अध्यक्ष नील लाल ने कहा, जब मंदिरों पर हमला होता है या हिंदू परिवारों पर फब्तियां कसी जाती हैं, तो यह केवल समुदाय पर हमला नहीं होता, बल्कि यह स्कॉटलैंड के सहिष्णुता मूल्यों पर आघात होता है। गांधीवादी संस्था ने इसे धार्मिक समानता की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है।

चीन ने धरती फाड़ी तो निकली सोने की खान ! वैज्ञानिकों की आंखें फटी रह गईं

बीजिंग, एजेंसी। 1,000 टन सोने का विशाल भंडार मिला, जिसकी कीमत अरबों डॉलर में बताई जा रही है। चीन के इस खुलासे के बाद भारत के पड़ोस में खनिज शक्ति का नया केंद्र बनता दिख रहा है। चीन के लिओनिंग प्रांत में भूगर्भशास्त्रियों ने 1,000 टन सोने का भंडार खोजा है। यह इलाका पूर्व से पश्चिम 3 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण 2.5 किलोमीटर में फैला है। यानी ये कोई छोटा-मोटा खजाना नहीं बल्कि 'धरती की तिजोरी' है जो अब खुल चुकी है।

वैज्ञानिकों का कहना है कि जहां-जहां ड्रिल की जा रही है, वहां-वहां सोने का अयस्क मिल रहा है। इससे ये साफ है कि सोने की सांद्रता बहुत अधिक हैऔर इसे निकालना भी बेहद आसान होगा। मतलब यह सोना केवल कागज पर नहीं, बल्कि वाकई जमीन के अंदर भरा पड़ा है।

ये खोज उस समय सामने आई है जब केवल कुछ महीने पहले ही चीन के हुनान प्रांत में भी 80 अरब डॉलर कीमत का सोना मिलने का दावा किया गया था। वहां सतह से करीब एक मील नीचे 40 सोने की नसें मिली थीं। अब लिओनिंग में ये नई खोज सामने आकर पूरे देश को संसाधनों के मामले में मजबूत कर रही है। चीन पहले से ही दुनिया का सबसे बड़ा सोना उत्पादक देश है, लेकिन भंडार के मामले में वो अब भी दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से पीछे है। लिओनिंग और हुनान में हुई ये खोजें उसे इस दौड़ में आगे बढ़ाने का काम कर सकती हैं। 2024 में चीन ने करीब 380 टन सोने का उत्पादन किया था, लेकिन ये नया खजाना उस आंकड़े को बहुत तेजी से बढ़ा सकता है। सोना सिर्फ गहनों या निवेश का साधन नहीं है, बल्कि यह एक देश की आर्थिक स्थिरता में भी बड़ी भूमिका

निभाता है। जब वैश्विक स्तर पर वित्तीय संकट आता है तब सोना ही एक मजबूत बैकअप बनता है। इसके अलावा ये बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने में भी उपयोगी होता है – और ये क्षेत्र चीन की औद्योगिक नीति के केंद्र में हैं। भारत के पड़ोस में इतनी बड़ी मात्रा में सोने का मिलना सिर्फ खनिज दृष्टि से नहीं बल्कि रणनीतिक रूप से भी चिंताजनक हो सकता है।

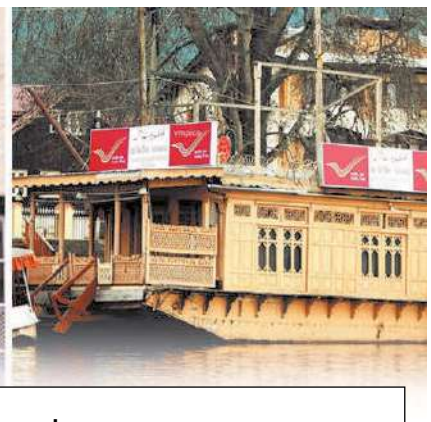

300 साल से चल रहा है दुनिया का सबसे पुराना डाकघर

क्या आप जानते हैं कि मंगोलिया में डाकघरों की संख्या कम होने के कारण वहां डाकिए पैदल, घोड़े या ऊँट की सवारी करके सुदूर इलाकों में डाक पहुंचाते हैं। यह दुनिया की सबसे कठिन डाक सेवा में से एक मानी जाती है। वहीं, नामीबिया में वाल्केन पोस्ट ऑफिस 600 साल पुराने बाओबाब वृक्ष के अंदर स्थित था और 1990 तक चालू स्थिति में था। भूटान में एक सोलर पोस्ट ऑफिस है, जो पर्यावरण अनुकूल डाक सेवाओं के लिए एक मिसाल है।

आज हमारे पास संचार के कई माध्यम हैं..मोबाइल फोन, ईमेल, सोशल मीडिया, वीडियो कॉल, वाट्सअप आदि। इनके ज़रिए हम तेज गति और आसानी से किसी से भी संपर्क कर सकते हैं। बावजूद इसके, इनमें वो मिठास और आत्मीयता नहीं हो जो हाथ से लिखी चिट्ठी में होती है। चिट्ठी सिर्फ हाथ से लिखा एक संदेश भर नहीं है, बल्कि एक अहसास है। जब हम किसी को खत लिखते हैं तो हर शब्द को सोच-समझकर चुनते हैं। इसमें हम अपने जज्बातों को खुलकर और विस्तार से ज़ाहिर कर सकते हैं। आपके हाथ से लिखे शब्दों की महक जब सामने वाले तर पहुंचती है, तो वो भी उनकी खूशबू से भीग जाता है। यही वजह है कि लोग सालोंसाल अपने प्रियजनों की चिट्ठियां संभालकर रखते हैं।

दुनिया के अनोखे डाकघर

आज के डिजिटल युग में जहां सब कुछ क्षणिक और व्यस्तताओं से भरा है, सुकून इस बात का है कि अब भी डाकघर बंद नहीं हुए हैं। अब भी कुछ लोग हैं जो खत लिखते हैं। अब भी पोस्ट ऑफिस में लोग जाते हैं। और जब बात हो रही है पोस्ट ऑफिस की तो आज हम आपको दुनिया के कुछ अनोखे और खास डाकघर के बारे में बताने जा रहे हैं।

हिम्मी डाकघर, चीन

यह दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित डाकघर है, जो 5,300 मीटर (17,388 फीट) की ऊंचाई पर तिब्बत पठार में स्थित है। यह डाकघर विशेष रूप से यात्रियों और पर्वतारोहियों के लिए आकर्षण का केंद्र है।

सबसे पुराना डाकघर, स्कॉटलैंड →

स्कॉटलैंड के छोटे से गांव Sanquhar में स्थित है दुनिया का सबसे पुराना डाकघर, जो वर्ष 1712 से लगातार चालू है। 18वीं शताब्दी में यह पोस्ट ऑफिस लंदन और एडिनबर्ग के बीच पत्र और दस्तावेजों के आदान-प्रदान के लिए स्थापित किया गया था। यह तब से लगातार चालू है, यानी इसे 300 से अधिक वर्षों से इस्तेमाल किया जा रहा है।

अंडरवाटर डाकघर, वानुआतु

वानुआतु के हिदेन आइलैंड पर स्थित यह दुनिया का पहला और इकलौता पानी के अंदर बना हुआ डाकघर है। इसे समुद्र में लगभग 3 मीटर (10 फीट) गहराई में स्थापित किया गया है। यहां वाटर प्रूफ पोस्टकार्ड भेजे जा सकते हैं, जिन्हें विशेष रूप से तैयार किया गया है।

पोर्ट लॉकरॉय डाकघर

इसे पेंगुइन पोस्ट ऑफिस भी कहा जाता है क्योंकि यह हजारों पेंगुइनों के बीच स्थित है। पर्यटकों के लिए ये बेहद आकर्षण का केंद्र है और वे यहां से दुनिया के किसी भी हिस्से में पत्र भेज सकते हैं। यह ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे के अधीन आता है और सर्दियों के दौरान बंद रहता है।

फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस, भारत

शुरुआत करते हैं भारत से। जम्मू-कश्मीर की डल झील (श्रीनगर) में दुनिया का इकलौता तैरता हुआ डाकघर है। इसे 2011 में स्थापित किया गया था और यह पानी में एक नाव पर बना हुआ है। ये डाकघर पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र रहता है।

सबसे छोटा डाकघर, अमेरिका

फ्लोरिडा के ओचोपी में दुनिया का सबसे छोटा डाकघर स्थिति है। इसका आकार सिर्फ 56 वर्ग फुट (5.2 वर्ग मीटर) है और यह पहले एक सिंचाई उपकरण स्टोररूम था। 1953 में एक आग लगने से स्थानीय डाकघर जल गया, जिसके बाद इस छोटे से स्टोररूम को डाकघर में बदल दिया गया।

जानवर को किस रंग में दिखाई पड़ती है दुनिया

रंगों का हम सभी के जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है। चाहे इंसान हो या जानवर सभी के लिए रंग की एक अलग प्रकाष्ठा होती है। इस दुनिया में हम अलग-अलग रंगों को देखते हैं, जिससे मन और दिमाग को अलग फील होता है। वहीं, अगर हम बात करें जानवरों की तो वह अलग-अलग रंगों का अनुभव नहीं कर पाते हैं। लेकिन सभी एक निश्चित रंग को देख पाते हैं। कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं, जिन्हें कोई एक पार्टिकुलर रंग नहीं नजर आता है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं।

कलर विजन

जानवरों में कलर विजन का लेवल शंकु की मौजूदगी और प्रकार पर पूरी तरह से डिपेंड करता है तो चलिए हम आपको उन रंगों के बारे में बताएंगे, जिन्हें अलग-अलग जानवर नहीं देख पाते हैं। सभी में रंगों के देखने की शक्ति और अनुभव विभिन्न होता है।

जानवरों में दो तरह के शंकु

सबसे पहले हम बात करते हैं, बिल्ली और कुत्ते की, तो इन जानवरों में दो तरह के शंकु होते हैं। इसलिए यह नीले और हरे रंग की रोशनी को महसूस कर पाते हैं। वहीं गाय की बात करें, तो उन्हें पीला और नीला रंग ही नजर आता है, लेकिन वह लाल रंग नहीं देख सकती। अब बात करते हैं भैंस की, तो यह लाल और भूरे रंग के अलावा कोई और रंग नहीं देख सकते। रंगों के अनुभव करने की लिस्ट में बैल भी शामिल है, जिन्हें लाल रंग बिल्कुल भी नजर नहीं आता है। इन्हें केवल हरा, नीला, वायलेट और पीला रंग दिखाई देता है।

जानें कारण

अब सवाल यह उठता है कि आखिर इन्हें लाल रंग क्यों नहीं दिखाई देता है, तो आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, जानवरों में लाल रेटीना रिस्पेक्टर की कमी होती है। यह सबसे बड़ा कारण है कि जानवरों को लाल रंग नजर नहीं आता। हालांकि, बचपन में लगभग हर किसी को इस बात का डर होता था कि बैल के सामने यदि आप लाल रंग का कपड़ा पहले जाते है तो आपको सिंह से मार देंगे, लेकिन इस बात में जरा सी भी सच्चाई नहीं है। उन्हें लाल रंग का कुछ भी नजर नहीं आता है।

रणजीत टाइम्स
08
इंदौर, बुधवार 23 अप्रैल 2025
DIGITAL EDITION

पीएम मोदी के स्वागत के लिए पहुंच गया एफ-15 फाइटर जेट

● सऊदी अरब में घुसते ही मोदी की दिल छूने वाली खातिरदारी

क्राउन प्रिंस ने भेजा एफ-15 विमान, पीएम की स्पेशल अगवानी

रियाद (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सऊदी अरब में जमीन पर उतरे नहीं थे कि क्राउन प्रिंस ने उनकी सुरक्षा के लिए अपने लड़ाकू विमान को भेज दिया। ये एक स्पेशल संकेत है। जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विमान को सऊदी हवाई क्षेत्र में रॉयल सऊदी वायु सेना के एफ 15 विमानों ने स्वागत किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में इसे स्पेशल जेस्चर बताया है। ट्वीट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की राजकीय यात्रा के विशेष सम्मान के रूप में, उनके विमान को सऊदी हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते ही रॉयल सऊदी वायु सेना द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सऊदी अरब को भारत के सबसे मूल्यवान साझेदारों में से एक बताया है और इसे एक विश्वसनीय मित्र और सहयोगी करार देते हुए कहा, कि वर्तमान समय उनके संबंधों के लिए आशाजनक समय है। जिसमें 'असीमित संभावनाएं' हैं। सऊदी अरब की अपनी दो दिवसीय यात्रा से पहले अरब न्यूज को दिए साक्षात्कार में मोदी ने कहा, ''भारत और सऊदी अरब न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे विश्व की शांति, प्रगति तथा समृद्धि के लिए एक साथ आगे बढ़ते रहेंगे।'' इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देश द्विपक्षीय निवेश संधि पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत और जीसीसी (खाड़ी सहयोग परिषद) के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते में भारत और सऊदी अरब तथा पूरे क्षेत्र के बीच आर्थिक संबंधों को बदलने की क्षमता हैं। इसके अलावा पीएम मोदी ने इस साझेदारी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सऊदी नेतृत्व की प्रशंसा की और निमंत्रण के लिए सऊदी अरब के शहजादे (क्राउन प्रिंस) मोहम्मद बिन सलमान को धन्यवाद दिया।

संसद ही सुप्रीम, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है

● उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बोले-सांसद असली मालिक

पहले कहा था-सुप्रीम कोर्ट सुपर संसद जैसे काम कर रही

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को लेकर चल रही बहस के बीच उप-राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मंगलवार को कहा कि संसद ही सबसे ऊपर है। धनखड़ दिल्ली यूनिवर्सिटी में संविधान पर आयोजित प्रोग्राम में स्पीच दे रहे थे। धनखड़ ने कहा, संसद सर्वोच्च है और उसके ऊपर कोई नहीं हो सकता। सांसद ही असली मालिक हैं, वही तय करते हैं कि संविधान कैसा होगा। उनके ऊपर कोई और सत्ता नहीं हो सकती। इससे पहले 17 अप्रैल को धनखड़ ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का काम ऐसा है, जैसे वो सुप्रीम संसद हो। धनखड़ का यह बयान तब आया है, जब सुप्रीम कोर्ट में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के बयान का मामला पहुंचा है। दुबे ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ऐसे में सीजेआई किसी राष्ट्रपति को निर्देश कैसे दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट और संसद के कार्यक्षेत्र को लेकर बहस तमिलनाडु सरकार और वहां के राज्यपाल के बीच विवाद से शुरू हुई थी। राज्य सरकार के बिल रोके जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल को समय सीमा के भीतर एक्शन लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को बिलों को लेकर राष्ट्रपति के लिए भी टाइम तय कर दी थी।

एमपी में बोलेरो पलटी, 5 बहनों समेत 8 की मौत

दमोह में जागेश्वर धाम के दर्शन कर जबलपुर लौट रहे थे; मोड़ पर खाई में गिरी गाड़ी

दमोह (एजेंसी)। दमोह के बनवार चौकी क्षेत्र में महादेव घाट के पास बोलेरो अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। मंगलवार सुबह करीब 11 बजे हुए हादसे में एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई। इनमें 5 बहनें शामिल हैं। 8 और 10 साल के दो बच्चों की भी जान गई है। पुलिस ने बताया कि जबलपुर के भीटा फूलर गांव का परिवार बांदकपुर से जागेश्वर धाम के दर्शन करने के बाद लौट रहा था। बोलेरो में 15 लोग सवार थे। इनमें से 6 की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दो बच्चों ने दमोह जिला अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। 5 अन्य घायलों को दमोह जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद जबलपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। उन्हें ग्रीन कॉरिडोर बनाकर दमोह से जबलपुर पहुंचाया गया।

एमपी में 1 मई से होंगे कर्मचारियों के तबादले

अगले हफ्ते आएगी ट्रांसफर नीति, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में जोड़ों की लिमिट तय की

भोपाल। मध्यप्रदेश में करीब ढाई साल बाद 1 से 31 मई तक कर्मचारियों के तबादले होंगे। मंगलवार को डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कैबिनेट बैठक की ब्रीफिंग के दौरान यह जानकारी दी। बैठक शुरू होने से पहले एक न्यूज एजेंसी से चर्चा में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी तबादलों से रोक हटाने के संकेत दिए थे। सीएम ने कहा, हमारी कोशिश रहेगी कि तबादला नीति अगली कैबिनेट बैठक तक आ जाए। बता दें, मध्यप्रदेश के कर्मचारी लंबे समय से तबादलों का इंतजार कर रहे हैं।

पिछले साल के अंत में कुछ विशेष मामलों में तबादलों की छूट दी गई थी, लेकिन इससे कई कर्मचारी वंचित रह गए थे। **विवाह/निकाह योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये संशोधनों को मंजूरी-** मंत्रि-परिषद द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये संशोधनों को मंजूरी दी गई। योजना अंतर्गत कन्या तथा कन्या के अभिभावक गरीबी रेखा के नीचे जीवन निर्वाह करते हों, साथ ही इनका बीपीएल पोर्टल पर सत्यापन अनिवार्य होगा। कन्या विवाह तथा निकाह सम्मेलन के लिये संभागवार वार्षिक चक्रीय रूप से कैलेण्डर जारी कर सामूहिक विवाह/निकाह कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा। संभागवार जिलों मे आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में सम्मिलित विवाह जोड़ों की न्यूनतम संख्या 11 एवं अधिकतम 200 जोड़ों की निर्धारित की गयी है। योजना में सामूहिक विवाह/निकाह सम्मेलनों में प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी पूर्व अनुसार निकाय स्तर पर की जाएंगी। पात्र/अपात्र एवं समग्र पोर्टल पर वर-वधू की आधार ई-केवायसी अनिवार्य होगा। सामूहिक विवाह कार्यक्रमों के लिये शासन की ओर से मिलने वाले आर्थिक लाभ को सार्थक बनाने का प्रयास करते हुये आयोजन में जन-प्रतिनिधियों एवं अन्य सामाजिक संस्थाओं की भागीदारी सुनिश्चित कर समाज के संपन्न और सक्षम व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त किया जायेगा। मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना में प्रति कन्या राशि 55 हजार रूपये में से वधू को राशि रुपये 49 हजार का एकाउन्ट पेयी चेक और शेष 6 हजार रुपये सामूहिक विवाह समारोह आयोजन के लिए संबंधित निकाय को प्रदाय किया जायेगा। सहायता राशि रुपये 49 हजार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से वधू के खाते में जमा की जाएगी।

एमपी परिवहन में बड़े बदलाव, वसूली का खेल

● 15 मिनट में करनी होगी जांच, लागू हो गए नए नियम

भोपाल। मध्य प्रदेश में अब परिवहन विभाग ने वाहनों की जांच के लिए नए नियम बना दिए हैं। ये नियम 21 अप्रैल 2025 से लागू हो गए हैं। इन नियमों के अनुसार, जांच करने वाले अधिकारियों को बॉडी वार्न कैमरे और पीओएस मशीन का इस्तेमाल करना होगा। जांच पूरी करने के लिए सिर्फ 15 मिनट का समय मिलेगा। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि अवैध वसूली को रोका जा सके और वाहन मालिकों को बेवजह परेशान न किया जाए। अगर किसी वाहन को ज्यादा देर तक रोका जाता है, तो उसका कारण बताना होगा।

परिवहन आयुक्त विवेक शर्मा ने ये नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इनके अनुसार, अब परिवहन चेक प्वाइंट और संभागीय परिवहन सुरक्षा स्क्वाड को 15 मिनट में वाहन की जांच पूरी करनी होगी। बिना किसी सही कारण के वाहन को ज्यादा देर तक नहीं रोका जा सकेगा। अगर रोकना पड़े, तो उसका कारण बताना होगा। एक गाड़ी की जांच पूरी होने के बाद ही दूसरी गाड़ी को रोका जा सकेगा। जांच के दौरान बॉडी वार्न कैमरे लगाना जरूरी है। कर्मचारियों को वर्दी पहननी होगी और उस पर नाम की प्लेट भी लगानी होगी। परिवहन आयुक्त के नए आदेश के अनुसार, जांच सिर्फ वर्दी पहने हुए अधिकारियों की मौजूदगी में ही होगी। जांच के दौरान कम से कम एक सहायक परिवहन उप निरीक्षक का होना जरूरी है। कर्मचारियों को वर्दी पहननी होगी और वर्दी पर नाम की प्लेट भी लगानी होगी। अगर इन नियमों का पालन नहीं किया गया, तो कार्रवाई की जाएगी। जांच के दौरान कोई भी प्राइवेट आदमी वहां नहीं रह सकता। रात में जांच करते समय, ऐसी जगह चुननी होगी जहां अच्छी रोशनी हो। स्टाफ को एलईडी बैटन और रिफ्लेक्टिव जैकेट दिए जाएंगे। परिवहन आयुक्त ने साफ कहा है कि अगर कोई इन नियमों को तोड़ेगा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। परिवहन विभाग के चेक प्वाइंट और उड़नदस्ते अब जांच की पूरी रिकॉर्डिंग करेंगे। जांच के दौरान दो कैमरे चालू रहेंगे। एक कैमरा लाइव मोड में रहेगा, जबकि दूसरा स्टैंड बाय मोड में रहेगा। कैमरों की निगरानी और रिकॉर्डिंग की जिम्मेदारी यूनिट प्रभारी की होगी। जांच की रिकॉर्डिंग को संभालकर रखना होगा और कैमरों को हमेशा चार्ज रखना होगा। लगभग एक साल पहले, मध्य प्रदेश में गुजरात मॉडल को लागू करते हुए परिवहन चौकियों को बंद कर दिया गया था। उनकी जगह अंतरराज्यीय सीमा पर 45 चेक प्वाइंट बनाए गए थे लेकिन यहां भी ट्रकों और वाहनों से अवैध वसूली की शिकायतें आने लगीं। इसलिए परिवहन आयुक्त ने जांच में पारदर्शिता लाने के लिए नए नियम जारी किए हैं।

वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिम संगठनों का प्रदर्शन

नई दिल्ली (एजेंसी)। नए वक्फ कानून के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मंगलवार को दिल्ली में प्रदर्शन कर रहा है। वक्फ बचाव अभियान के तहत तालकटोरा स्टेडियम में तहफ्फुज-ए-औकाफ कारवां (वक्फ की हिफाजत) नाम से आयोजन हुआ है। कार्यक्रम में जमात-ए-इस्लामी हिंद समेत देशभर के मुस्लिम संगठनों के अध्यक्ष और प्रतिनिधि पहुंचे हैं। इसमें असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हुए हैं। बैठक में वक्फ कानून के खिलाफ आगे की कानून लड़ाई लड़ने को लेकर चर्चा हो रही है।

सुबह 10 बजे से शुरू हुई बैठक करीब 2 बजे तक चलेगी। इधर, वक्फ कानून के विरोध के बीच दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति बोले- लोकतंत्र में संविधान को चुनौती स्वीकार नहीं। सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों को समझाना होगा। अगर नहीं समझे तो कड़वी दवा का स्वाद चखना होगा। बोर्ड के वक्फ बचाव अभियान का पहला फेज 11 अप्रैल से शुरू हुआ, जो 7 जुलाई यानी 87 दिन तक चलेगा। इसमें वक्फ कानून के विरोध में 1 करोड़ हस्ताक्षर कराए जाएंगे, जो पीएम मोदी को भेजे जाएंगे। इसके बाद अगले फेज की रणनीति तय की जाएगी।